THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K. C. LENKA): (a) and (b) Three cases of unlawful possession of khoya were detected and 415 kg. of khoya was seized by Delhi Administration.

(c) Yes, Sir.

(d) In course of intensive checkings made during May, June and July (till 19.7.91), 8 FIRs were lodged and 12 persons arrested.

(e) Cases are under investigations and further action as per law will be taken by the UT Administration.

Subernerekha multi-purpose Project (Bihar)

1764. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item entitled "VMV men on hunger-strike" which appeared in the Statesman, New Delhi, dated 10th July, 1991;

(b) the World Bank team now on a visit at Chandil, near Jamshedpur, to examine the second phase of the Subernerekha multipurpose project has expressed concern about the socio-environmental impact of the project as the project formulated does not include activities to rehabilitate the families displaced by the project; as indicated by the World Bank team to members of Visthapit Mukti Vahini, a local voluntary organisation; and

(c) in view of the resource crunch what steps Government proposes to take to reformulate the project by taking into account fresh requirements from the socio-environmental angle in order that funds are not blocked and the project is expedited?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYACHARAN SHUKLA): (a) Yes, Sir.

(b) The World Bank Team, which visited the States of Bihar and Orissa in connection with the second phase of the Subernerekha Multipurpose project, has not commented adversely on the environmental impact of the Project. On the other hand, they have expressed satisfaction with the policies formulated by the States of Bihar and Orissa with regard to rehabilitation and resettlement. They have also stressed the need to implement these policies quickly. The Visthapit Mukti Vahini has since withdrawn their agitation.

(c) After taking into account the socio-environmental concerns, the project has been planned to be constructed in phases matching with the availability of resources.

Privatisation of Steel plant/under SAIL

1765. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) in what manner liberalisation of the economy and adherence to market forces would affect the State owned steel plants;

(b) what would be the effect of each of the different large steel plants under Steel Authority of India Limited;

(c) whether there is any move to privatise wholly or partially the steel plants under Steel Authority of India Limited; and

(d) if not, whether there is going to be any effect on Steel Authority of India Limited of the new economic philosophy, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SANTOSH MOHAN DEB): (a) and (b) Liberalisation and greater effect of market forces, would in general, imply greater competition for the state owned steel plants. In this scenario, SAIL's steel plants would need to take steps to upgrade their technological status, increase their efficiency, effect economies

in costs of operations and production and strive to become more competitive both in domestic and international markets. This would apply uniformly to all the steel plants in the Public Sector including SAIL.

(c) and (d) While at present there is no proposal for privatisation of any of the SAIL steel plants, this is only one aspect of the Government's liberalisation policy. SAIL have taken due note of other features of the new economic policy of the Government the effect of which would only be known over a period of time.

टिस्को द्वारा उत्पाद शुल्क का अपवंचन

1766. **श्री राम अवधेश सिंह:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा समूह अपने लोहे और इस्पात के प्राइम उत्पादन के 12 प्रतिशत भाग को "टिस्को रिजेक्टिड" चिन्हित करके उसे अपनी एजेंसियों के माध्यम से बेच कर प्राइम इस्पात की कीमत वसूल करता है और इस प्रकार वह उत्पाद शुल्क का अपवंचन करता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार रेंज के केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी तथा जमशेदपुर में तैनात उत्पाद शुल्क अधिकारी टाटा समूह के साथ सांठगांठ कर के उत्पाद शुल्क का बड़े पैमाने पर घोटाला करता है ; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी संसदीय समिति से कराने और प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की राजस्व की हानि को रोकने का विचार रखती है, और क्या सरकार जमशेदपुर और रांची स्थित उत्पाद शुल्क अधिकारियों के आवासों पर छापे मारने का विचार भी रखती है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देब) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मैसर्स खेतान को मिक्स्ड कोक की बिक्री

1767. **श्री राम अवधेश सिंह:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक अपना कार्यभार सौंपने से कुछ दिन पूर्व समस्त प्रक्रियाओं और मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य का 1.85 लाख टन मिक्स्ड कोक मैसर्स खेतान को बेच दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इतनी बडी मात्रा में कोक बेचने का सौदा बिक्री संबंधी किसी प्रक्रिया का पालन न करके केवल धन के लेन देन के आधार पर तय किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त प्रबंध निदेशक और स्टील अथारिटी आफ इंडिया के वर्तमान वाणिज्य निदेशक ने बंगलोर में एक बहुत बड़ी सात मंजिली इमारत का निर्माण कराया है , जिसकी लागत उनके ज्ञात आय स्त्रोतों से बहुत ज्यादा है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर "हां" हो तो सरकार इन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है ; क्या उन्हें उनके वर्तमान पद से मुक्त कर दिया जाएगा और बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंध निदेशक के रूप में उनके क्रियाकलापों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराई जाएगी ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देब) : (क) और (ख) एकमत प्रस्ताव और एकमात्र मध्यस्थ पंचाट के आधार पर बोकारो इस्पात संयंत्र के तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने 28 मार्च, 1990 को संशोधित बिक्री आर्डर को स्वीकृत किया था ताकि मैसर्स स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड 13,97,22, 400/- रु० मूल्य का 1,74,653 टन मिश्रित